



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1984/वंशांक 11, 1906

No. 202]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1984/VAISHAKHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1984

अधिसूचनाएं

का० आ० 338 (अ):—“दल खालसा” के नाम से ज्ञात संघटन—

(1) जिसने एक संपूर्ण स्वायत्त “खालसा राज्य” स्थापित करना अपना मुख्य उद्देश्य घोषित किया था, अपने उद्देश्य के अनुसरण में भारत के एक भाग को बिलग करने और अपने सक्रियतावादियों के माध्यम से संघ की राज्यसोपरीय अखंडता को विच्छिन्न करने का प्रचार करना रखा है।

(2) जिसके पदाधिकारी और सक्रियतावादी एक पृथक राज्य “खालिस्तान” की रचना का समर्थन खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाकर और भारतीय राष्ट्रीयता ध्वज को जलाने और खालिस्तान के पृथक राज्य के उद्देश्यों से अभिवृद्धि करने वाली सभाओं और प्रदर्शनों जैसे क्रियाकलापों के माध्यम से करते हैं।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से “दल खालसा” एक विधिविरुद्ध संगम है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि “दल खालसा” के पदाधिकारियों और सक्रियतावादियों द्वारा खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और अन्य क्रियाकलापों के कारण, “दल खालसा” को तत्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक हो गया है;

133 GI/84—1

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निषेध) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “दल खालसा” को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन देती है कि यह अधिसूचना उस आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[एफ० सं० 4/12/84-टी]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st May, 1984

NOTIFICATIONS

S.O. 338(E).—Whereas the organisation known as ‘Dal Khalsa’—

- (i) which had declared as its main objective the establishment of a complete autonomous ‘Khalsa State’ has, in pursuance of its objective, been preaching secession

(1)

and disruption of the territorial integrity of India through its activities ;

- (ii) whose office-bearers and activists have extended support to the creation of 'Khalistan', a separate State, by raising pro-Khalistan slogans and through such activities as burning the Indian national flag and participating in gatherings and demonstrations to promote the cause of a separate State of Khalistan ;

And Whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the 'Dal Khalsa' is an unlawful association :

And Whereas the Central Government is further of the opinion that because of the raising of pro-Khalistan slogans and other activities of the office-bearers and activists of the 'Dal Khalsa', it is necessary to declare the 'Dal Khalsa' to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'Dal Khalsa' to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the official Gazette.

[File No. 4/12/84-T]

का०आ० 339 (अ) :—नेशनल काउन्सिल आफ खालिस्तान (जिसे इसमें इसके पश्चात काउन्सिल कहा गया है) के नाम से ज्ञात संगठन :—

(1) जिसने उसके महासचिव, श्री बलबीर सिंह संधू की घोषणा के माध्यम से एक स्वशासी, अलग सिख राज्य "खालिस्तान की स्थापना करना अपना उद्देश्य उद्घोषित किया था, "दल खालसा" नाम से ज्ञात संगठन के विलगकारी और हिंसात्मक क्रियाकलापों का प्रोत्साहन करता रहा है ;

(2) जिसका महासचिव, श्री बलबीर सिंह संधू समाचार पत्रों के संवाददाताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ अपने वार्तालाप में और 26 जनवरी, 1984 को तथा कथित खालिस्तान को तत्स्थित ढाज को फहरा कर अलग राज्य "खालिस्तान" की मांग का समर्थन करता रहा है ;

(3) जिसमें अध्यक्ष, श्री अगजोत सिंह चौहान ने श्री बलबीर सिंह संधू को काउन्सिल के नए अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में निष्ठा या और जिसने तथाकथित "खालिस्तान" गणराज्य के राज बिम्ब वाला पत्र भी जारी किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि "पूर्वोक्त कारणों से काउन्सिल एक विधिविरुद्ध संगम है ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि "काउन्सिल" के अध्यक्ष और महासचिव के वार्तालाप, कथन, लेखन और अन्य क्रियाकलापों के कारण "काउन्सिल की तत्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक" हो गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल काउन्सिल आफ खालिस्तान को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि यह अधिसूचना उस आदेश के अधीन रहने हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[एफ०सं० 4/12/84-उ०.]

एल० एन० गुप्ता, संयुक्त सचिव

S.O. 339(E).—Whereas the organisation known as the 'National Council of Khalistan' (hereinafter referred to as the Council)—

- (i) which had through the declaration of Shri Balbir Singh Sandhu, its Secretary General, proclaimed as its objective the establishment of an autonomous, separate Sikh State of "Khalistan" has been encouraging the secessionist and violent activities of the organisation known as 'Dal Khalsa' ;
- (ii) whose Secretary General, Shri Balbir Singh Sandhu has been extending support to the demand for 'Khalistan', a separate State in his talks with newspaper correspondents and others and by hoisting a flag purporting to be the flag of the so-called Khalistan on the 26th January, 1984 ;
- (iii) whose President, Dr. Jagjit Singh Chauhan had written to Shri Balbir Singh Sandhu regarding election of a new President for the Council and who had also issued a paper carrying the insignia of the so-called Republic of Khalistan ;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Council is an unlawful association ;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the talks, utterances, writings and other activities of the President and Secretary General of the Council, it is necessary to declare the Council to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'National Council of Khalistan' to be an unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 4/12/84-T]

L. N. GUPTA, Joint Secy.